शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 मार्च 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सम्पादकीय

विज्ञान युग में 'ग्रामवाद' से रुकेंगी किसानों की आत्महत्याएं

डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

मध्यप्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। विधानसभा में जानकारी दी गई है कि विभिन्न कारणों से 829 किसानों ने आत्महत्या की है। मध्यप्रदेश को विगत चार वर्षों से गेहूं की अच्छ पैदावार के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है तो दूसरी ओर किसानों की आत्महत्या से हमारा सिर शर्म से झुक रहा है। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की बात जाने दीजिए, अब तो शहरी सीमा से लगे गांवों से भी किसानों की आत्महत्या के समाचार आ रहे हैं। यह दुष्चक्र सोयाबीन की फसल के खराब होने से शुरू हुआ। मध्यप्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में सिरमौर रहा है। जब सोयाबीन नहीं था, तब मालवा और मध्यप्रदेश में अन्य फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास हुआ करती थीं। सोयाबीन के आने के बाद किसानों ने इन फसलों को लगाना बंद कर दिया। यद्यपि सोयाबीन ने किसानों को समृद्ध किया, परंतु अब मौसम परिवर्तन ने सोयाबीन की फसल पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। विगत चार वर्षों से सोयाबीन की फसल ठीक से नहीं हो रही है। किसानों ने जमा पंूजी और बैंक आदि से लिए गए कर्ज को सोयाबीन की फसल में लगाया। मौसम की मार ने सोयाबीन का उत्पादन कम कर दिया। जब किसान उसे बाजार में लेकर गया तो उसे क्वालिटी का हवाला देकर कम भाव दिया गया। सोयाबीन विक्रय से जो राशि प्राप्त हुई, उसे गेहूं की फसल में लगा दिया। बेमौसम बारिश ने गेहूं की फसल पर पानी फेर दिया। सरकार ने समय पर न तो सर्वे किया और न पर्याप्त राहत राशि की व्यवस्था की। फलतः किसान तनाव में चला गया और उसका परिणाम हमें किसानों की आत्महत्या में दिखाई दे रहा है। आज का किसान मौसम और सरकार पर निर्भर हो गया है। ग्रामीण जनता ने अपना अभिक्रम खो दिया है। सरकार मुखापेक्षी होने से किसानों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। विज्ञान के जमाने में ग्राम परिवार भावना का विकास करना आवश्यक है। इसके बिना हमारे ग्रामीण किसान जी नहीं सकेंगे। ग्राम परिवार एक अत्यंत व्यावहारिक चीज है। गांव वालों को यदि सच्चे अर्थ में गांव की उन्नति की चाह है और वे गांव को सर्वांगीण बनाकर उसे राष्ट्र की सुदृढ़ नींव बनाना चाहते हैं तो ग्राम परिवार की भावना को क्रियान्वित करना चाहिए। आज एक ही वाद की आवश्यकता है और वह है 'ग्रामवाद'। केंद्रीय बजट में गांव के लिए लगभग 36 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सत्य है कि अगर कहीं एक जगह सत्ता हो और वही सब गांवों की योजना करे तो गांवों की समस्याएं कभी हल नहीं सकतीं। सारा आयोजन ग्रामीणों की बुद्धि से ही होना चाहिए। स्थान विशेष की परिस्थिति देखकर लोग अपने-अपने हित की योजना बनाएं। इसी का नाम विकेंद्रित योजना है और यह गांव की उन्नति का आधार है। हरेक गांव अपने यहां ग्राम पंचायत में दो साल का अनाज का भंडारण रखे। जिससे सूखा आदि प्राकृतिक आपदा के समय उस अनाज का उपयोग जीवित रहने के लिए किया जा सके।